भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
24.07.2024 के
तारांकित प्रश्न सं. 36 का उत्तर

मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत रेल लाइनें

***36. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या सरकार ने मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत बसई से दिवा रेल लाइन बिछाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;**

(ख) **यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;**

(ग) **उपरोक्त रेल लाइन बिछाने के लिए अधिगृहीत की गई कुल भूमि का ब्यौरा क्या है; और**

(घ) **उक्त रेल लाइन बिछाने की समयावधि और अनुमानित लागत के संबंध में विस्तृत जानकारी क्या है?**

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्‌योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत रेल लाइनों के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे के तारांकित प्रश्न सं. 36 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): वसई से दिवा खंड पहले से ही दोहरी बड़ी आमान लाइन का रेलखंड है। इसके समानांतर संरेखण पर पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके अलावा, नायगांव और जुचांद्रा (5.73 किलोमीटर) के बीच वसई बाईपास लाइन (दोहरी लाइन) के निर्माण को भी स्वीकृत कर दिया गया है। उपनगरीय गलियारों पर भावी मांगों के लिए इन गलियारों का आगे और विस्तार करना सतत् प्रक्रिया है। इसके अलावा, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के भाग के रूप में महाराष्ट्र सरकार के साथ 50:50 लागत में साझेदारी के आधार पर 7,184 करोड़ रुपए की लागत पर पनवेल-विरार नए उपनगरीय गलियारे पर भी विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा, उपनगरीय गलियारों पर संकुलन से बचने और भावी मांगों को पूरा करने के लिए, 10,947 करोड़ रुपये की लागत वाला एमयूटीपी-III और 33,690 करोड़ रुपये की लागत वाला एमयूटीपी-IIIए को स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित 10 अतिरिक्त रेल लिंक शामिल हैं :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1	सीएसटीएम-कुर्ला 5वीं एवं 6ठी लाइन (17.5 कि.मी.)	891
2	मुंबई सेंट्रल-बोरीवली 6ठी लाइन (30 कि.मी.)	919
3	पनवेल-करजत उपनगरीय गलियारा (29.6 कि.मी.)	2782
4	एरोली-कलवा (एलीवेटेड) उपनगरीय गलियारा लिंक (3.3 कि.मी.)	476
5	विरार-दहाणु रोड की 3री एवं 4थी लाइन का चौहरीकरण (64 कि.मी.)	3587
6	हार्बर लाइन गोरेगांव-बोरीवली का विस्तार (7 कि.मी.)	826
7	बोरीवली-विरार 5वीं एवं 6ठी लाइन (26 कि.मी.)	2184
8	कल्याण-आसनगांव के बीच 4थी लाइन (32 कि.मी.)	1759
9	कल्याण-बदलापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन (14.05 कि.मी.)	1510
10	कल्याण यार्ड-मेन लाइन और उपनगरीय लाइन का पृथक्करण	866

s.k

इन सभी एमयूटीपी परियोजनाओं को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच लागत में 50:50 भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार 2022-23 तक प्रतिबद्धता के अनुसार समय पर अपेक्षित धनराशि प्रदान नहीं कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2023 से एमयूटीपी-IIIए परियोजनाओं का वित्तपोषण शुरू कर दिया है।

रेल परियोजनाओं को राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत किया जाता है क्योंकि भारतीय रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। बहरहाल, 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 81,580 करोड़ रुपए की लागत से 5,877 कि.मी. कुल लंबाई की 41 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरण में हैं, जिसमें से 1,926 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 31,236 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैः-

i. 8,529 करोड़ रु. की लागत पर 2,017 कि.मी. कुल लंबाई की 16 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 166 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 8,529 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

ii. 7,339 करोड़ रु. की लागत पर 609 कि.मी. कुल लंबाई की 2 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 312 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 3,332 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

iii. 35,818 करोड़ रु. की लागत पर 3,251 कि.मी. लंबाई की 23 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 1448 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 19,376 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं का लागत, निधियों के स्रोत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेलवे-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	1171 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2014-24	7197 करोड़ रु. प्रति वर्ष	6.1 गुना
2023-24	13539 करोड़ रु.	11.56 गुना

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की कमीशनिंग का ब्यौरा निम्नानुसार है -

अवधि	कमीशन किए गए कुल रेलपथ	कमीशन किए गए औसत रेलपथ	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	292 किलोमीटर	58.4 किलोमीटर प्रति वर्ष	-
2014-24	1830 किलोमीटर	183 किलोमीटर प्रति वर्ष	3.13 गुना

2023-24 में कुल 358 कि.मी. को कमीशन किया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में 6 गुना से अधिक है।

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करना।

****

s.k